बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग

करनाल। करनाल कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता महंगाई का दंश झेल रही है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पानी के बिलों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की जेब पर डाका डालने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। सरकार का फोकस बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों पर होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर जिले पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जलभराव से लोगों को खाने-पीने के सामान से लेकर बिजली-पानी और मवेशियों के चारे तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इधर सरकार ने लोगों की जेब खाली करने की योजना बना डाली है।

त्रिलोचन सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा में लाखों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। करनाल जिले के गांवों में भारी नुकसान हुआ है। जल निकासी के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाए।

उन्होंने कहा कि किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। मकानों, दुकानदारों और कारोबारियों को हुए नुकसान का भी उचित आकलन करके सभी को मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो।

देश में बाढ़ आ गई, मोदी जी कहां गए?

त्रिलोचन सिंह ने कहा कि भारी बरसात के चलते देश के अधिकतर राज्यों में बाढ़ आ गई है। लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी हैं। करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आ गया है। इन हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के नागरिकों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए पीएम केयर फंड का खजाना खोल देना चाहिए।

मगर खेद की बात है पीएम देश से ही बाहर चले गए हैं। स्वयं को प्रधान सेवक और देश का चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री आपदा के समय देश के नागरिकों की परवाह नहीं कर रहे। विदेशों में लोगों के बीच जाकर उनको राहत देने का प्रयास कर रहे हैं।

जाम सीवर और बजबजाते नाले दे रहे करोड़ों रुपये डकारे जाने की गवाही

नगर निगम ने केवल नौ वार्डों की सफाई में बहाए 4,64,98,353 रुपये, फिर भी जलभराव और सीवर जाम की समस्या

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) विकास कार्यों के नाम पर दो सौ करोड़ रुपये के घोटालों से जूझ रहे नगर निगम में लूट कमाई का खुला खेल आज भी जारी है। शहर के नौ वार्डों में सीवर लाइन और नाला सफाई के लिए करीब 4.65 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए बावजूद इसके सारा शहर बरसात में पानी में डूब गया। बरसात में शहर भर में हुए जलभराव ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। खास बात यह कि सीवर लाइनों की सफाई के लिए एक साल के लिए जारी टेंडर में अभी भी करीब छह महीने का समय बाकी है लेकिन पूरा साल बीत गया और कहीं भी सीवर लाइन साफ नहीं हुई।

स्मार्ट सिटी में बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था, साफ-सुथरे नाले, गड्ढा मुक्त सड़कें, शुद्ध पेयजल आपूर्ति के नाम पर कई सौ करोड़ रुपये बर्बाद करने वाले निगम के भ्रष्ट अधिकारी बरसात गुजरने के बाद ही नाला और सीवर सफाई कराते हैं इसमें करोड़ों रुपयों का खेल किया जाता है।

बीते वर्ष नगर निगम अधिकारियों ने बरसात गुजर जाने के बाद वार्ड 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 और 21 में नाला सफाई व सीवर लाइन की सर्विस कराने के लिए टेंडर जारी किए। इसमें नालों की सफाई 27 सितंबर से 26 दिसंबर के बीच किए जाने का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही इन वार्डों में सीवर लाइनों की सफाई काम काम

भी सौंपा गया। सबसे ज्यादा पैसा यानी करीब चार करोड़ रुपया इन्ही सीवर लाइनों की सफाई के नाम पर जारी किया गया। सीवर सफाई का यह काम 7 अक्तूबर 2022 से 8 अक्तूबर 2023 तक किया जाना है।

करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद इन वार्डों सहित पूरे शहर में सीवर जाम की समस्या बनी हुई है। बरसात में तो हालात और भी बुरे हो जाते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला कहते हैं कि एनआईटी एक, दो, तीन और पांच में तो सीवर लाइनें आरएमसी रोड के नीचे दबा दी गई हैं। बिना सड़क तोड़े इन्हें साफ नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि निगम अधिकारी और ठेकेदार इस इलाके की सीवर लाइन साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपये डकार रहे हैं। आरटीआई से जुटाए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि यदि सीवर और नाला सफाई का गंभीरता से ऑडिट कराया जाए तो करोड़ों रुपये का एक अन्य घोटाला सामने आ जाएगा।

सीवर सफाई की ही तरह नाला सफाई में भी घोटाला किया जाता है। उनके अनुसार भ्रष्ट निगम अधिकारियों को नालों की सफाई मानसून शुरू होने से पहले करानी चाहिए थी लेकिन टेंडर 27 सितंबर से नाला सफाई करने का जारी किया गया, बहाना बताया गया कि सर्दी में बरसात होने पर नालों में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रहे। नाला सफाई के नाम केवल औपचारिकता की गई और ठेकेदार व अधिकारी के बीच धन की बंदरबांट हो गई।

बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, थोड़ी सी बरसात में ही सारा शहर पानी में डूब जाता है। डबुआ कॉलोनी में चंद साल पहले ही बनाया गया नाला आज भी सिल्ट और गंदगी से पटा पड़ा है यही कारण है कि थोड़ी सी बरसात में पूरा डबुआ रोड लबालब हो गया। यही हालात शहर के सभी नालों का है। सबसे ज्यादा बुरे हाल तो बाटा चौक से मुजेसर फाटक के बीच की सड़क का है, मुजेसर फ्लाई ओवर के पास आम दिनों में ही जलभराव बना रहता है बरसात के दिनों में तो यहां के हालात बदतर होते हैं जबकि यहां सफाई के नाम लाखों रुपये खर्च करने का ड्रामा किया जाता है। रवींद्र चावला इस घोटाले को उजागर करने के लिए सीएम विंडो पर शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं।

6 अगस्त को होने वाली कांग्रेस रैली की तैयारियां

करनाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल की जनता के साथ 6 अगस्त को जन संवाद करेंगे इसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी लोगों से रूबरू होंगे कार्यक्रम का आयोजन एसबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड में किया जाएगा जनसंवाद कार्यक्रम के लिए न्योता देने सुमिता सिंह पूर्व विधायक करनाल ने दराबी लाइन सदर बाजार रिंकू सोदा प्रधान के निवास पर एकत्रित लोगों को जनसंवाद कार्यक्रम के लिए बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

इस मौके पर सुमिता सिंह ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है आम आदमी की थाली से धीरे-धीरे खाने का सब सामान गायब हो रहा है दाल, आटा, तेल, दूध, टमाटर, मिर्ची अदरक मसाले सब के दाम आसमान छू रहे। बिजली के बढ़ते बिल, स्कूल की बढ़ती फीस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है आम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है!

गरीब आदमी टमाटर की चटनी बना कर खा लेता था लेकिन टमाटर पेट्रोल से भी महंगा हो गया है ! जो टमाटर किसान से दो रुपए किलो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था और किसान को दुखी होकर अपना टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ता था वो आज कहीं 200 तो कहीं कहीं 300 के पार बिक रहा है। 200 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर वही है जो किसान से दो रुपये किलो में खरीदा गया जा, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों की चांदी हो गई है और सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है।

सुमिता सिंह ने कहा कि जो सरकार आम लोगों के खाने की दो वक्त की रोटी को भी महंगा कर दें इस सरकार को सत्ता में एक पल भी रहने का हक नहीं है। बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। कांग्रेस सरकार के समय गैस का सिलेंडर 350 रुपये हुआ तो भाजपा नेता सिर पर रखकर प्रदर्शन करते थे अब सिलेंडर का दाम 1100 के पार चला गया है तो भाजपा नेताओं की बोलती क्यों बंद हो गई उन्होंने कहा कि सरकार आसमान छूती महंगाई से कराह रही जनता को राहत देने की बजाय पेट्रोल, डीजल ,रसोई गैस और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बढ़ाती जा रही है । इस अवसर पर प्रधान रिंकू सौदा, मोनू कल्याण ,सागर भूमबक,रजत सौदा ,जुगनी , सनी सोनकर, बॉबी बिड़ला न, सुशील सोनकर, रमन सहोता ,खुशी गोरी, सौरव सौदा ,गौतम लोट, रजनीश सारसर, मनोहर लाल, शिवा वैद्य, पम्मी बिरला न आदि मौजूद थे।

अम्मा अस्पताल ने छीन ली ग्रेफ वासियों की बिजली

220 केवीए का सब स्टेशन एक तिहाई क्षमता के साथ शुरू हुआ, आधी बिजली अम्मा अस्पताल को दी गई

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) धार्मिक-पूंजीवादियों के सामने नतमस्तक खट्टर सरकार इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नागरिकों के हित तक छीनने में लगी है। कई साल से सब स्टेशन की मांग कर रहे ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों का हक मारते हुए खट्टर सरकार के बिजली निगम ने पहले अम्मा अस्पताल को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी। बिजली निगम के अधिकारियों ने ग्रेफ वासियों को इसकी जानकारी तक नहीं होने दी।

ग्रेटर फरीदाबाद की 50 हाईराइज कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवार लंबे समय से 220 केवीए का सबस्टेशन स्थापित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। कॉलोनी बनने के साथ ही बिजली आपूर्ति और कनेक्शन का शुल्क भी ये लोग जमा करा चुके हैं। हुड्डा सरकार के समय से बिजली आपूर्ति कराए जाने की मांग कर रहे ग्रेफ वासियों को उस समय खुशी हुई थी जब खट्टर सरकार ने यहां 220 केवीए सब स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की थी। इन बेचारों को नहीं मालूम था कि खट्टर सरकार उनके लिए नहीं बल्कि अम्मा अस्पताल को बिजली आपूर्ति देने के लिए ये नाटक कर रही है।

दरअसल, फरवरी में शुरू हुए अम्मा के फाइव स्टार अस्पताल में बिजली आपूर्ति के लिए जेनरेटर सेट में रोजाना लाखों रुपये का डीजल खर्च हो रहा था। ऐसे में अम्मा अस्पताल वालों ने मुख्यमंत्री खट्टर से बिजली आपूर्ति कराने को कहा। खट्टर ने भी आज्ञाकारी भक्त की तरह डीएचबीवीएन को तुरंत ही अम्मा अस्पताल को बिजली आपूर्ति करने का हुक्म सुना दिया। बस फिर क्या था जिस सब स्टेशन को पृथला से बिजली आपूर्ति की जानी थी उसे आनन-फानन अस्थायी रूप से ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट की फीडर लाइन से जोड़ दिया गया। समस्या ये थी कि यहां से केवल 70 केवीए यानी सब स्टेशन की क्षमता की महज एक तिहाई ही बिजली आपूर्ति मिली। इसके साथ ही अम्मा अस्पताल को 35 केवीए बिजली तुरंत ही उपलब्ध करा दी गई। लंबे अर्से से बिजली की मांग कर रहे ग्रेफ वासियों को डीएचबीवीएन के अधिकारियों ने इसकी भनक भी नहीं लगने दी और न ही दूसरी सोसायटियों को बिजली दी गई। माना जा रहा है कि यदि दूसरी सोसायटियों को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई तो संभव है कि अधिक मांग के कारण लो वोल्टेज की समस्या हो सकती है जिससे अम्मा अस्पताल की बिजली आपूर्ति बाधित होगी, खट्टर के अधिकारी आम जनता को तो परेशान देख सकते हैं लेकिन अम्मा को नहीं।

अब जब अम्मा अस्पताल की बिजली आपूर्ति की समस्या सुलझ गई है तो ग्रेफ वासियों को पृथला से बिजली आने तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो काफी लंबा खिंच सकता है क्योंकि पृथला से सेक्टर 78 तक सब स्टेशन तक लाइन खींचे जाने में अभी बहुत समय लगेगा। दरअसल बिजली निगम और किसानों के बीच पोल लगाने के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को लेकर विवाद हो गया है और काम रुका हुआ है।

गौरतलब है कि ये 220 केवीए का सब स्टेशन भी खट्टर जी अपने घर से नहीं बनवा रहे, इसके निर्माण का पैसा यहां रहने वाले

लोगों से बरसों पहले बिल्डरों के माध्यम से वसूला जा चुका है। सर्वविदित है कि बिल्डरों एवं कॉलोनाइजरों को लाइसेंस जारी करते समय बाहरी विकास तथा आंतरिक विकास के रूप में मोटी वसूली अग्रिम रूप में कर ली जाती है। बीसियों वर्ष पहले सैकड़ों करोड़ की यह वसूली हरियाणा सरकार करके डकार चुकी है। इसके बावजूद ग्रेटर फरीदाबाद अधिकांश सोसायटियां डीजल जेनरेटर सेट की महंगी बिजली का खर्चा भुगतने को मजबूर हैं। जानकार बताते हैं कि ग्रेटर फरीदाबाद में इस तरह के तीन से अधिक विद्युत सबस्टेशन स्थापित किए जाने हैं जिनका पैसा भी यहां के नागरिकों से वसूला जा चुका है।